भारत सरकार
मत्स्यपालन ,पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2909
18 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए निधि

2909. श्री गौरव गोगोई:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बेलोरटोल डंपिंग साइट से होने वाले प्रदूषण के कारण दीपोर बील की मछली विविधता गंभीर खतरे में है, जिससे आर्द्रभूमि में विषाक्त पदार्थ निकलते हैं;

(ख) क्या सरकार ने यह देखते हुए कि दीपोर बील 50 से अधिक देशी मछली प्रजातियों का आवास है, ठोस अपशिष्ट डंपिंग के कारण मछली की आबादी पर पड़ने वाले प्रभाव पर कोई वैज्ञानिक मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने दीपोर बील में प्रदूषण कम करने और मछली जैव विविधता बहाल करने के लिए मत्स्यपालन या आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत कोई धनराशि आवंटित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(श्री जॉर्ज कुरियन)

(क) से (ग): असम के दीपोर बील में विषाक्त प्रदूषण के बारे में मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में कोई विशेष रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

इसके अलावा, आईसीएआर-सेंट्रल इनलैंड फिशरीज़ रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीआईएफआरआई) ने दीपोर बील से 21 प्रकार के 55 देशी मत्स्य प्रजातियों की उपलब्धता दर्ज की है। इस विभाग को दीपोर बील में मत्स्य जैव विविधता की बहाली पर कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। असम सरकार द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, गुवाहाटी नगर निगम (जीएमसी) ने वेटलैंड रिजुवनेशन, बायोरेमेडिएशन और हैबिटेट रेस्टोरेशन के लिए 172.50 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ 'बोरागांव में लैंडफिल खनन' पर एक परियोजना शुरू की है जो कि राज्य के स्वामित्व में प्राथमिकता वाली विकास योजना है और असम सरकार द्वारा वित्त पोषित है ।

*****